भारत सरकार
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2012
30 जुलाई, 2026 को उत्तर देने के लिए

फसलोपरांत होने वाली हानि, खाद्य प्रसंस्करण अवसंरचना तथा किसानों की आय

†2012. **डॉ. प्रभा मल्लिकार्जुन:**

क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने देश में कृषि एवं बागवानी उत्पाद में फसलोपरांत होने वाली हानि का कोई आकलन किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) विगत पांच वर्षों के दौरान स्थापित शीत-श्रृंखला सुविधाओं, खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों, एकीकृत पैक हाउसों, फूड पार्कों तथा कृषि-प्रसंस्करण अवसंरचना का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने किसानों की आय, मूल्य संवर्धन, रोजगार सृजन तथा अपव्यय में कमी पर खाद्य प्रसंस्करण अवसंरचना के प्रभाव का मूल्यांकन किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) खाद्य प्रसंस्करण पारितंत्र को सुदृढ बनाने, फसलोपरांत होने वाली हानि को कम करने तथा किसानों के लिए बाजार तक पहुंच में सुधार करने हेतु किए जा रहे उपायों का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्या कर्नाटक, विशेषकर दावणगेरे जिले में किसी एकीकृत खाद्य प्रसंस्करण, शीत-श्रृंखला, मेगा फूड पार्क अथवा कृषि-प्रसंस्करण परियोजना को स्वीकृति प्रदान की गई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री
(श्री चिराग पासवान)

(क) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय (एमओएफपीआई) द्वारा प्राथमिक सर्वेक्षणों के आधार पर अध्ययन के माध्यम से देश में विभिन्न कृषि उत्पादों के फसल कटाई के बाद होने वाले नुकसान का समय-समय पर आकलन किया जाता है। मंत्रालय द्वारा दो अध्ययन शुरू किए गए : (i) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) - केंद्रीय कटाई-उपरांत अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी संस्थान (सीआईपीएचईटी), 2015 (संदर्भ वर्ष 2012-14) और (ii) नाबार्ड कंसल्टेंसी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड (नैब्कॉन्स), 2022 (संदर्भ वर्ष 2020-22)। इन अध्ययनों की रिपोर्टों के अनुसार, इसमें शामिल विभिन्न कृषि और बागवानी उत्पादों की फसल कटाई और फसल कटाई-उपरांत होने वाले नुकसान का अनुमानित प्रतिशत इस प्रकार है :

प्रमुख फसलों और वस्तुओं का कटाई-उपरांत नुकसान

फसलें/वस्तुएं	**हानि प्रतिशत में**	
	आईसीएआर-सीआईपीएचईटी अध्ययन (वर्ष 2015) के अनुसार*	**नैब्कॉन्स अध्ययन (वर्ष 2022) के अनुसार****
अनाज	4.65 - 5.99	3.89-5.92
दालें	6.36 - 8.41	5.65-6.74
तिलहन	3.08 - 9.96	2.87-7.51
फल	6.70-15.88	6.02-15.05
सब्ज़ियाँ	4.58-12.44	4.87-11.61
बागान फसल और मसाले	1.18-7.89	1.29-7.33
दूध	0.92	0.87
मत्स्य पालन (अंतर्देशीय)	5.23	4.86

मत्स्य पालन (समुद्री)	10.52	8.76
मांस	2.71	2.34
मुर्गी पालन	6.74	5.63
अंडा	7.19	6.03

स्रोत: *भारत में प्रमुख फसलों और वस्तुओं की मात्रात्मक फसल कटाई और कटाई-पश्चात नुकसान के आकलन पर रिपोर्ट, 2015. ** नैब्कॉन्स अध्ययन वर्ष 2022

(ख) केंद्रीय क्षेत्र की अम्ब्रेला योजना - प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना (पीएमकेएसवाई) के अंतर्गत, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय (एमओएफपीआई) प्रसंस्करण और परीक्षण अवसंरचना के निर्माण के लिए खाद्य प्रसंस्करण परियोजनाओं की स्थापना हेतु अनुदान/सब्सिडी के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान करता है। पीएमकेएसवाई (पीएमकेएसवाई) की घटक योजनाओं के अंतर्गत, पिछले पांच वर्षों के दौरान स्थापित शीत श्रंखला सुविधाओं, खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों, फूड पार्कों और कृषि-प्रसंस्करण अवसंरचना का राज्य-वार विवरण **अनुबंध-I** में संलग्न है।

(ग) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय (एमओएफपीआई) समय-समय पर देश में खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र की समग्र स्थिति की जांच करने, अपनी चल रही योजनाओं के कार्यान्वयन और प्रभाव का मूल्यांकन करने, और फसल कटाई के बाद होने वाले नुकसान को निर्धारित करने के लिए चुनिंदा वस्तुओं के प्रसंस्करण स्तरों का आकलन और अनुमान लगाता रहा है। हालाँकि, अब तक खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय (एमओएफपीआई) ने विशेष रूप से किसानों की आय, मूल्यवर्धन, रोजगार सृजन और बर्बादी में कमी पर खाद्य प्रसंस्करण अवसंरचना के प्रभाव का आकलन नहीं किया है।

(घ) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय (एमओएफपीआई) प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना (पीएमकेएसवाई), प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम उन्नयन (पीएमएफएमई) और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन योजना (पीएलआईएसएफपीआई) जैसी विभिन्न पहलों और योजनाओं के कार्यान्वयन के माध्यम से देश भर में खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के समग्र विकास का लक्ष्य रखता है। एमओएफपीआई अपनी योजनाओं के माध्यम से, देश भर में किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) और सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) सहित पात्र संस्थाओं को सहायता अनुदान/प्रोत्साहन प्रदान करता है। इन योजनाओं का उद्देश्य खेत से लेकर खुदरा दुकानों तक कुशल आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन के साथ आधुनिक अवसंरचना का निर्माण करना है। इन योजनाओं में भंडारण, परिवहन और बाज़ार संपर्क स्थापित करना आदि शामिल हैं, ताकि फ़सल कटाई के बाद होने वाले नुकसान को कम करने, किसानों की आय बढ़ाने और खेती से इतर रोज़गार के अवसर पैदा करने में सहयोग मिल सके।

एमओएफपीआई के अलावा, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने फसल कटाई के बाद के बुनियादी ढांचे में सुधार और सामुदायिक खेती की परिसंपत्ति बनाने के लिए आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत जुलाई 2020 में कृषि अवसंरचना कोष (एआईएफ) योजना शुरू की है। एआईएफ योजना बैंकों और अन्य ऋणदाता संस्थानों द्वारा शीत भंडारण सुविधाओं, गोदामों और प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना के लिए मध्यम से दीर्घकालिक ऋणों की मंजूरी को सुगम बनाती है, जिसका उद्देश्य फसल की बर्बादी को कम करना, मूल्यवर्धन को बढ़ाना और किसानों को बेहतर आय प्रदान करना है।

(ङ) पीएमकेएसवाई की घटक योजनाओं के अंतर्गत कर्नाटक में स्वीकृत परियोजनाओं का विवरण **अनुबंध-II** में है। 'कृषि प्रसंस्करण क्लस्टर अवसंरचना (एपीसी) योजना' के अंतर्गत मेसर्ज जेम फ़ूड पार्क एलएलपी की एक परियोजना कर्नाटक के दावणगेरे ज़िले में स्थित है, जिसकी परियोजना लागत 40.01 करोड़ रुपये है।

****

अनुबंध- ।

लोक सभा में दिनांक 30 जुलाई, 2026 को उत्तर हेतु फसलोपरांत होने वाली हानि, खाद्य प्रसंस्करण अवसंरचना तथा किसानों की आय, के संबंध में अतारांकित प्रश्न संख्या 2012 के भाग (ख) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध।

तालिका-1: पिछले पांच वर्षों (2021-2022 से 2025-2026) के दौरान स्वीकृत और पूर्ण हुई शीत श्रृंखला परियोजनाओं का राज्य-वार विवरण

क्र.सं.	राज्य/केंद्र शासित प्रदेश	स्वीकृत	पूर्ण/प्रचालनरत			
			संख्या	स्वीकृत जीआईए (करोड़ रुपये में)	जीआईए जारी (करोड़ रुपये में)	परियोजना लागत (करोड़ ₹ में)
1	अंडमान और निकोबार	0	0			
2	आंध्र प्रदेश	11	17	144.09	143.36	723.26
3	अरुणाचल प्रदेश	1	0	-	-	-
4	असम	0	0	-	-	-
5	बिहार	0	0	-	-	-
6	चंडीगढ़	0	0	-	-	-
7	छत्तीसगढ़	2	0	-	-	-
8	दादर और नगर हवेली और दमन और दीव	0	0	-	-	-
9	दिल्ली	0	0	-	-	-
10	गोवा	0	0	-	-	-
11	गुजरात	6	6	48.27	47.86	188.32
12	हरियाणा	5	7	59.43	58.93	253.50
13	हिमाचल प्रदेश	0	4	38.94	38.46	95.09
14	जम्मू और कश्मीर	2	2	7.46	7.46	18.15
15	झारखंड	0	0	-	-	-
16	कर्नाटक	5	2	12.95	12.95	48.00
17	केरल	4	1	9.63	9.63	27.31
18	लद्दाख	0	0	-	-	-
19	लक्षद्वीप	0	0	-	-	-
20	मध्य प्रदेश	1	5	39.79	38.76	101.89
21	महाराष्ट्र	15	13	82.02	81.96	327.03
22	मणिपुर	0	0	-	-	-
23	मेघालय	0	0	-	-	-
24	मिज़ोरम	0	0	-	-	-
25	नागालैंड	0	0	-	-	-
26	उड़ीसा	5	3	28.70	28.16	136.26
27	पुडुचेरी	0	0	-	-	-
28	पंजाब	4	5	20.16	20.16	85.31
29	राजस्थान	1	2	9.20	9.20	25.73
30	सिक्किम	0	0	-	-	-
31	तमिलनाडु	11	7	49.98	49.98	194.95
32	तेलंगाना	5	6	47.82	47.82	239.24
33	त्रिपुरा	0	0	-	-	-
34	उत्तर प्रदेश	5	7	52.71	51.30	206.17
35	उत्तराखंड	1	6	57.26	57.26	110.12
36	पश्चिम बंगाल	5	4	30.70	30.70	129.82
	कुल	**89**	**97**	**739.11**	**734.15**	**2910.15**

तालिका-2: पिछले पांच वर्षों (2021-2022 से 2025-2026) के दौरान कृषि प्रसंस्करण क्लस्टर (एपीसी) योजना के अंतर्गत स्वीकृत और पूर्ण हुई परियोजनाओं का राज्य-वार विवरण

क्र.सं.	राज्य/केंद्र शासित प्रदेश	स्वीकृत परियोजनाएँ	पूर्ण/प्रचालनरत			
			पूर्ण परियोजनाएँ	स्वीकृत जीआईए (करोड़ रुपये में)	जीआईए जारी (करोड़ रुपये में)	परियोजना लागत (करोड़ ₹ में)
1	अंडमान और निकोबार	0	0	0	0	0
2	आंध्र प्रदेश	3	0	0	0	0
3	अरुणाचल प्रदेश	0	0	0	0	0
4	असम	3	2	16.7357	14.6629	39.9768
5	बिहार	0	0	0	0	0
6	चंडीगढ़	0	0	0	0	0
7	छत्तीसगढ़	1	0	0	0	0
8	दादर और नगर हवेली और दमन और दीव	0	0	0	0	0
9	दिल्ली	0	0	0	0	0
10	गोवा	0	0	0	0	0
11	गुजरात	3	3	17.42	13.1987	59.968
12	हरियाणा	0	1	3.09	2.7610	10.26
13	हिमाचल प्रदेश	1	0	0	0	0
14	जम्मू और कश्मीर	0	0	0	0	0
15	झारखंड	0	0	0	0	0
16	कर्नाटक	3	1	9.77	6.9256	40.01
17	केरल	0	2	18.9485	18.0262	71.72
18	लद्दाख	0	0	0	0	0
19	लक्षद्वीप	0	0	0	0	0
20	मध्य प्रदेश	0	2	19.8	14.0842	57.68
21	महाराष्ट्र	4	4	37.313	33.91	121.04
22	मणिपुर	0	0	0	0	0
23	मेघालय	0	0	0	0	0
24	मिज़ोरम	0	0	0	0	0
25	नागालैंड	0	0	0	0	0
26	उड़ीसा	1	1	10	9.7749	50.524
27	पुडुचेरी	0	0	0	0	0
28	पंजाब	0	1	6.7598	5.1452	27.44
29	राजस्थान	3	0	0	0	0
30	सिक्किम	0	0	0	0	0
31	तमिलनाडु	4	3	21.2288	19.6046	83.6575
32	तेलंगाना	3	0	0	0	0
33	त्रिपुरा	0	0	0	0	0
34	उत्तर प्रदेश	0	1	10	9.729	21.05
35	उत्तराखंड	0	0	0	0	0
36	पश्चिम बंगाल	0	0	0	0	0
	कुल	**29**	**21**	**171.0658**	**147.8223**	**583.3263**

तालिका-3: खाद्य प्रसंस्करण और परिरक्षण क्षमता सृजन/विस्तार योजना के अंतर्गत पिछले पांच वर्षों (2021-2022 से 2025-2026) के दौरान स्वीकृत और पूर्ण हुई परियोजनाओं का राज्य-वार विवरण।

क्र.सं.	राज्य/केंद्र शासित प्रदेश	स्वीकृत परियोजनाएँ	पूर्ण/प्रचालनरत			
			परियोजना लागत (करोड़ ₹ में)	स्वीकृत जीआईए (करोड़ रुपये में)	जीआईए जारी (करोड़ रुपये में)	परियोजना लागत (करोड़ ₹ में)
1	अंडमान और निकोबार	0	0	0	0	0
2	आंध्र प्रदेश	14	6	29.04	28.91	351.985
3	अरुणाचल प्रदेश	6	1	1.21	1.17	3.37
4	असम	40	43	170.94	165.26	582.093
5	बिहार	6	3	14.59	14.22	64.083
6	चंडीगढ़	0	0	0	0	0
7	छत्तीसगढ़	3	1	3.74	3.74	16.04
8	दादर और नगर हवेली और दमन और दीव	0	1	3.64	3.47	26.34
9	दिल्ली	0	0	0	0	0
10	गोवा	0	1	2.89	2.76	12.45
11	गुजरात	28	24	89.22	85.72	342.297
12	हरियाणा	12	14	43.02	41.99	192.311
13	हिमाचल प्रदेश	3	12	39.19	37.80	100.1
14	जम्मू और कश्मीर	0	11	32.91	31.32	79.81
15	झारखंड	0	0	0	0	0
16	कर्नाटक	19	12	45	43.62	178.95
17	केरल	17	18	62.37	60.46	240.76
18	लद्दाख	0	0	0	0	0
19	लक्षद्वीप	0	0	0	0	0
20	मध्य प्रदेश	12	6	24.15	23.91	81.387
21	महाराष्ट्र	57	53	190.37	185.98	751.11
22	मणिपुर	1	2	1.94	1.93	5.87
23	मेघालय	0	1	4.61	4.61	9.92
24	मिज़ोरम	0	1	3.54	3.19	9.35
25	नागालैंड	0	0	0	0	0
26	उड़ीसा	9	6	18.62	18.38	42.15
27	पुडुचेरी	0	0	0	0	0
28	पंजाब	13	9	38.42	37.70	296.84
29	राजस्थान	20	9	31.06	30.54	132.54
30	सिक्किम	0	0	0	0	0
31	तमिलनाडु	23	14	37.22	35.85	134.70
32	तेलंगाना	25	11	47.52	46.91	310.83
33	त्रिपुरा	1	5	14.50	14.38	37.92
34	उत्तर प्रदेश	20	24	88.53	83.19	369.21
35	उत्तराखंड	23	15	59.20	57.78	187.99
36	पश्चिम बंगाल	12	12	44.70	43.55	204.03
	कुल	**364**	**315**	**1142.14**	**1108.34**	**4764.436**

अनुबंध- II

लोक सभा में दिनांक 30 जुलाई, 2026 को फसलोपरांत होने वाली हानि, खाद्य प्रसंस्करण अवसंरचना तथा किसानों की आय, के संबंध में उत्तर हेतु अतारांकित प्रश्न संख्या 2012 के भाग (ङ) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध।

क्र.सं.	**परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी (पीईए) का नाम**	**ज़िला**	**परियोजना लागत (करोड़ में)**	**अनुदान स्वीकृत (करोड़ में)**	**कुल अनुदान जारी (करोड़ में)**
कृषि-प्रसंस्करण क्लस्टर अवसंरचना योजना (एपीसी) के लिए	मेसर्स जेम फूड पार्क एलएलपी	दावणगेरे	40.01	9.77	6.92565
	मेसर्स उडुपी फूड पार्क	उडुपी	16.08	5.23	3.7516
	मेसर्स श्री लक्ष्मीबालाजी एग्रो पार्क प्राइवेट लिमिटेड	कोप्पल	36.34	10	6.16
	मनदीप एग्री फूड पार्क एलएलपी	विजयपुरा	36.94	8.56	0
	अगरथा मेगा फूड पार्क एलएलपी	बैंगलोर रूरल	48.67	10	0
खाद्य प्रसंस्करण एवं परिरक्षण क्षमता सृजन/विस्तार योजना (सीईएफ़पीपीसी)	मेसर्स हैन फ्यूचर नेचुरल प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड	तुमकुर	36.76	5.00	4.79
	मेसर्स पेटंट फूड प्रोसेसर्स प्राइवेट लिमिटेड	तुमकुर	18.05	4.71	4.49
	मेसर्स एला फूड्स	कोलार	16.72	3.59	3.50
	मेसर्स रामकृष्ण इंडस्ट्रीज	बागलकोट	6.76	1.95	1.85
	मेसर्स स्प्राउटलाइफ फूड्स प्राइवेट लिमिटेड	तुमकुर	15.83	5.00	4.83
	मेसर्स संक्रमन ऑर्गेनिक फूड्स प्राइवेट लिमिटेड	मंड्या	7.84	1.42	1.36
	मेसर्स आरजी कासट इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड	बागलकोट	9.06	2.55	2.42
	मेसर्स अश्वरूदा एनरिच फूड्स	मंड्या	5.07	1.06	0.52
	मेसर्स श्री वेंकटेश्वर इंडस्ट्रीज	मैसूर	7.56	2.40	2.40
	श्री बालाजी इंडस्ट्रीज	मैसूर	6.86	2.25	2.25
	मेसर्स अवंतनेचर फूड्स प्राइवेट लिमिटेड	तुमकुर	9.33	2.36	2.31
	मेसर्स मैक्सविटा फूड्स (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड	मंड्या	18.91	4.42	4.28

	मेसर्स ट्रुबेयर फ्रेश फूड्स प्राइवेट लिमिटेड	तुमकुर	10.25	4.48	4.04
	मेसर्स ग्रोफ्रेश एग्रोफूड्स प्राइवेट लिमिटेड	तुमकुर	12.376	4.85	4.85
	मेसर्स वीबी फूड्स	बेंगलुरु शहरी	10.12	3.70	3.52
	मेसर्स एल्वीटी प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड	धारवाड़	18.06	4.89	4.89
	मेसर्स टेंगुराजा कोको प्रोडक्ट्स	उडुपी	11.48	5.00	4.75
	मेसर्स जुब्लिएंट फूड वर्क्स लिमिटेड	बैंगलोर रूरल	49.88	5.00	5.00
	मेसर्स श्रीदेवी जनरल इंजीनियरिंग	बैंगलोर रूरल	13.04	5.00	2.50
	मेसर्स कनिष्क बेवरेजेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	बैंगलोर रूरल	13.26	4.99	0.00
	मेसर्स श्री लक्ष्मीबालाजी एग्रो पार्क प्राइवेट लिमिटेड यूनिट- 1	कोप्पल	21.03	5.00	2.50
	मेसर्स श्री लक्ष्मीबालाजी एग्रो पार्क प्राइवेट लिमिटेड (यूनिट- 2)	कोप्पल	17.50	4.83	2.42
	मेसर्स एलन काजू इंडस्ट्रीज	उडुपी	10.53	4.38	4.27
	मेसर्स परिशुद्ध इंडस्ट्रीज	उडुपी	8.70	4.11	3.98
	मेसर्स श्री लक्ष्मीबालाजी एग्रो पार्क प्राइवेट लिमिटेड यूनिट-III	कोप्पल	20.8	5.00	2.50
	मेसर्स स्टार हाई हर्ब्स प्राइवेट लिमिटेड	हसन	16.57	4.94	0.00
	मेसर्स विजयलक्ष्मी एग्रो फूड्स	रायचूर	9.45	2.50	0.00
	मेसर्स विजयपुरा न्यूट्रीफूड्स एलएलपी	विजयपुरा	12.72	2.81	0.00
	मेसर्स आरजी कासट इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड	बगलकोट	10.45	1.94	0.00
	मेसर्स महादेव एग्रो इंडस्ट्रीज	रायचूर	25.00	4.71	0.00
	मेसर्स ईशा फूड्स	बैंगलोर रूरल	19.9	5.00	0.00
	मेसर्स द सेंट्रल एरेकॉट एंड कोको मार्केटिंग एंड प्रोसेसिंग को-ऑपरेटिव लिमिटेड	दक्षिण कन्नड़	12.04	4.22	0.00
	मैग्गेमेन फूड्स एलएलपी	हसन	17.36	5	0.00

	अथर्वस ट्रेडर्स प्राइवेट लिमिटेड	हसन, बेलगाम , बैंगलोर	28.61	7.50	7.50
	इनोवा एग्री बायो पार्क लिमिटेड	कोलार	14.00	3.36	3.36
	विजयकांत डेयरी और खाद्य उत्पाद लिमिटेड	बेलगाम	8.66	2.80	2.80
	बसवेश्वर उद्योग	बेलगाम	18.20	7.80	7.80
	नामधारी एनिमल जेनेटिक्स प्राइवेट लिमिटेड	तुमकुर	18.38	3.92	3.92
	डेयरी क्लासिक आइसक्रीम प्राइवेट लिमिटेड	रामनगर	29.81	7.61	7.61
	श्रीकृष्ण मिल्क्स प्राइवेट लिमिटेड	उत्तर कन्नड़	26.96	5.67	5.67
	मालपेफ्रेश मरीन एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड	उडुपी	18.10	4.37	4.37
	हाईटेक फूड प्रोसेस (एससी)	बीजापुर	15.00	8.46	8.46
	आइडियल आइसक्रीम	दक्षिण कन्नड़	36.54	9.86	9.86
	यशस्वी फिश मील एंड ऑयल कंपनी	दक्षिण कन्नड़	73.05	10.00	10.00
	बामुल	रामनगर	49.45	7.26	7.26
	एग्रो टेक (एसटी)	बेलगाम	15.38	10.00	6.50
	स्कायर मील प्राइवेट लिमिटेड	बैंगलोर	9.97	3.57	3.57
	गोल्डन हैचरीज़	हावेरी	38.03	9.38	9.38
खाद्य प्रसंस्करण एवं परिरक्षण क्षमता सृजन/विस्तार योजना (सीईएफ़पीपीसी)	प्रोविट फूड्स प्राइवेट लिमिटेड	दक्षिण कन्नड़	55.40	9.91	0.00
	नव्या इंडस्ट्री	विजयपुरा	26.81	10.00	3.33
	माइक्रोट्रोल स्टरलाइज़ेशन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड	तुमकुर	36.71	6.76	0.00
	मेसर्स नेत्रा डेयरी प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड	बेलगावी	63.02	10.00	0
	मेसर्स चतुर्मुख डेयरी प्राइवेट लिमिटेड	विजयपुरा	33.62	9.14	0.00
मेगा फूड पार्क योजना (एमएफपी)	इंटीग्रेटेड फूड पार्क लिमिटेड	तुमकुर	144.33	48.72	48.72
	फेवोरिच इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड	मंड्या	87.10	43.55	37.57